[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

है और इस तरह से महिला नर्सों का हमारा समाज और हमारी सरकार और हमारा रक्षा मंत्रालय शोषण कर रहा है । इसलिए इस गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान खींचते हुये आपके माध्यम से मैं सरकार और विशेष रूप से रक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सैनिक अस्पतालों में काम करने वाली महिला नर्सों के साथ जो यह भद-पूर्ण व्यवहार किया जाता है, अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जाता है, इसको तत्काल बन्द किया जाय और महिला नर्सों को शादी करने की अनुमति उसी प्रकार से दी जाये जिस प्रकार से पुरुष नर्सों को दी गई है, जिस प्रकार से पुरुष और महिला डाक्टरों को दी गई है ।

श्री मोहम्मद खलीलरररहमान (आंध्र प्रदेश) : वाइस-चैयरमन साहब, श्री पी० एन० सुकुल ने जो अपने स्पेशल मेंशन में कहा है उससे मैं अपने को एसोसिएट करता हूं ।

Need to develop Tourism on the West Coast of Karnataka

SHRI R. S. NAIK (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the House to the development of tourism on the West Coast of Karnataka. Sir, India has already crossed the target of one million foreign tourists during last year and we want to achieve the target of 2.5 mllion tourists by 1990 so that we could earn a lot of foreign exchange. But un'esg we provide the necessary infrastructure and make all efforts to maintain the flow of tourists to India, foreigners will not be attracted. When the foreign tourists return to their countries, they should carry more of our cultural heritage. India has a very great potential and it is very rich as far as places of tourists interest are concerned.

Karnataka has about 300 kms. of sea shore right from Mangalore to Kar-war, that is from the South to the North, known as the West Coast. Nature has gifted Karnataka with many natural scenic beauties and beautiful beaches in this region which attract both foreign and domestic tourists. The Government of India deputed a study team to Karnataka in 1987 headed by Mr. N. *K.* Sen Gupta, the then Director-General of Tourism in New Delhi, to study the potential in the West Coast region. This study team, after visiting the Karnataka coastal region, recommended many places in the region to be developed as beach resorts in the region in order to attract both domestic and foreign tourists. Among them are: Maravante in the South Kanara District which has got beautiful natural surroundings with sea shore separated by land about half a km. wide. Secondly, Mur-deshwar in the North Kanara District which is a pilgrim centre having a stone temple with beautiful carvings on a rock extending into the sea which is visited by people from all walks of life. Thirdly, international tourist resorts at Belegeri in the North Kanara District. Fourthly, development of beach resorts and development of a water sports complex in Karwar and development of Karwar beach etc.

The Karnataka Government has decided to develop Karwar as a beach resort in order to divert tourist traffic from Goa. Necessary reports in respect of some of these schemes had been sent to the Government of India on 21.6.1988 by the Karnataka Government with the request to accept the proposals and accord sanction under the Centrally-sponsored schemes. Karnataka has a very rich potential as far as places of tourist interest are concerned. Therefore, I would request the Government of India, through you, to accept the proposals sent by the Karnataka Government and accord sanction, giving Central assistance.

Nowadays, there has been a lot of sea erosion. When and where sea erosion will take place is uncertain, unknown and it cannot also be

•dieted because it is a natural calamity. It is also not possible for the State Government alone to check sea erosion because a huge amount will have to be spent. So, I request the Central Government to have an independent and separate scheme and allocation of more funds for 1.00P.M. checking sea erosion. Move allocation of funds be made in the coming budget. Konkati railwayline which comes from Bombay and connects Manglore and coastal region of Karnataka be completed as early as possible to strengthen tourism in Karnataka.

With these few words I conclude.

Agitation by Doctors/Medical teachers in Rajasthan

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस विशेष उल्लेख के द्वारा लोक हित का अत्यावश्यक मुद्दा भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में लम्बे समय से क्लीनिकल शिक्षक चिकित्सा अधिकारियों एवं नोन-क्लीनीकल शिक्षक चिकित्सा अधिकारियों की हड़ताल के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो चुकी है और जनता बड़ी परेशान है । समस्या का कारण यह बना है कि चौथे वेतन आयोग के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स का वेतनमान तो काफी अच्छा बढ़ गया और और उस बढ़े हुए वेतनमान को राज्य सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके वेतन के भुगतान में 80 प्रतिशत की भागीदारी युनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन की होती है एवं 20 प्रतिशत ही राशि राज्य सरकारों द्वारा दी जानी होती है । परन्तु इसके विपरीत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत शिक्षक चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान शिक्षा जगत में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स के मुकाबले में नहीं बढ़ा है । यह वास्तव में विडम्बना का विषय है कि शिक्षा जगत में कार्यरत लेकचरर्स एवं प्रोफेसर्स जो केवल ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर पद ग्रहण कर लेते हैं उसके विपरीत डाक्टर्स बनने के लिए उनको शिक्षा के क्षेत्र में लम्बा संघर्ष करना पड़ता है और उसके उपरान्त ही चिकित्सा अधिकारी लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स हो पाते हैं । इस प्रकार चिकित्सा जगत में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स भी शिक्षा जगत में आर्टस, कोमर्स साईन्स इत्यादि में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स के ही समानन्तर वेतन पाने के अधिकारी हैं बल्कि उनको (डाक्टर्स) अधिक वेतन मिलना चाहिये । चूंकि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति गम्भीर होने से उनके द्वारा चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान बढ़ाना एक समस्या है इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस मामले में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप कर समानान्तर पद वाले व्यक्तियों को समानान्तर वेतन मिलने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । केन्द्रीय सरकार के लिए भी सभी राज्यों की व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है । परन्तु राजस्थान के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजस्थान में पिछले चार पांच वर्षों से लगातार अकाल की गम्भीर समस्या होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और इस कारण राज्य सरकार का मानस डाक्टरों के वेतनमान को बढ़ाने का होने के उपरान्त भी वह बढ़ा नहीं पा रही है । उपरोक्त चिकित्सा अधिकारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गत वर्ष भी नोटिस दिया था परन्तु शताब्दी का भीषणतम अकाल होने के कारण उन्होंने उस समय अपना हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया था और राज्य सरकार ने उनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भेजा था एवं युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को भी अधिक वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा था । यह सब होने पर भी अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप इस वर्ष यह समस्या पुनः उत्पन्न हो गई है और डाक्टर्स हड़ताल पर चले गये हैं जिसको लगभग तीन सप्ताह हो चुके हैं । अस्पतालों में मरीजों की हालत बहुत गम्भीर है एवं चिकित्सा सुविधाओं की समय पर उपलब्धी नहीं होने के कारण काफी मरीज दम